OFFICE OF THE DISTRICT JUDGE, ALLAHABAD

Admin. Order No. 285 /2017 **Dated :** May 23, 2017

ORDER

Sri Chitra Sen Yadav, delinquent employee has moved a representation against his suspension stating that he is sole bread earner of his family. His wife is ill, his daughter aged about 24 years and is student of M. Sc. I year of Allahabad University and having marriageable age. His son is 17 years old and is a student of High School. Due to his suspension, education of his children and maintenance of his family is not possible. Delinquent employee prays for revoking his suspension order dated 26.05.2001.

Sri Chitra Sen Yadav, Class III employee attached in Family Court, Allahabad has been suspended in compliance of order dated 25.05.2001 passed by Hon'ble the Administrative Judge, Allahabad regarding complaint of Kiran Kumar dated 22.05.2001 regarding loss of records of Case No. 21 of 1998 Kiran Kumar Vs. Smt. Suman, Execution Case No. 157 of 2000 Saraswati Devi Vs. Munna Lal. Hon'ble the Administrative Judge, Allahabad has been pleased to pass following order in the matter :

> *"Having regard to the allegations made by the complainant and the report of the Judge, Family Court, Allahabad, I direct the Principal Judge, Family Court, Allahabad to initiate disciplinary proceeding against the delinquent employee and suspend him in the mean time till the conclusion of the departmental proceedings and will submit a further report."*

After receiving the letter dated 26.05.2001 of Sri N. K. Singh, the then Registrar (Confidential); the then Principal Judge, Family Court, Allahabad vide order dated 26.05.2001 initiated a departmental enquiry against Sri Chitra Sen Yadav and suspended him till the completion of departmental proceedings.

The then District Judge has approved a Charge-sheet having 8 charges against the delinquent employee on 27.08.2005 after about 4 years of the suspension of the delinquent employee.

After initiation of aforesaid departmental enquiry no. 14/F/2002, the then Additional District & Sessions Judge, Court Room No. 9 has submitted a report on 05.07.2013 and it is submitted that charge no. 3, 5 and 8 have been proved against the delinquent employee, other charges have not been proved. Charges no. 3, 5 and 8 against Sri Chitra Sen Yadav are reproduced as under :

"**तृतीयः**—यह कि दिनांक 24/07/2000 से दिनांक 11/08/2000 तक की अवधि के मध्य निष्पादन एवं प्रकीर्ण पत्रावलियों की एक सूची पारिवारिक न्यायालय के प्रबन्धक द्वारा वाद लिपिक श्री मंगलेश एवं प्रतिलिपिक अब्दुल रहमान जाफरी के सहयोग से बनाई गयी, क्यों कि आप ने इस न्यायालय द्वारा समस्त पत्रावलियों का भार प्रबन्धक को 3 दिन में सौंपने के आदेश के बावजूद भी न इस सम्बन्ध में प्रेषित सूचना पत्र का लिखित उत्तर दिया था और न ही पत्रावलियां प्रबन्धक के अध्यासन में दिये जाने के आदेश का ही अनुपालन किया था। प्रबन्धक द्वारा आप के अध्यासन में स्थित पत्रावलियों की सूची बनाने पर प्रबन्धक द्वारा यह पाया गया कि लगभग 239 पत्रावलियां इस प्रकार की थीं, जिनमें या तो आपके द्वारा आदेश पत्रों को खाली छोड़ दिया गया था, अथवा पीठासीन अधिकारी महोदया के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था, तथा पत्रावलियों को बिना किसी तिथि के रखा हुआ था तथा रिकवरी वारण्ट भी जारी नहीं किये गये थे। इस सम्बन्ध में जब आपसे स्पष्टीकरण मांगा गया तो दिनांक 17/08/2000 को आप ने यह लिखकर जवाब दिया कि 'आप के पूर्व आदेश के खिलाफ प्रार्थी माननीय उच्च न्यायालय जा चुका है, जहां से स्थगन आदेश आ चुका है और हमारे व आप के बीच मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।' आपने अपने जवाब में पीठासीन अधिकारी महोदया को यह भी लिखकर दिया कि 'जब तक माननीय उच्च न्यायालय का कोई फैसला नहीं हो जाता है, मैं आपके किसी प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं। आप आगे प्रार्थी का जवाब तलब करने की कृपा न करें।' इस प्रकार आपने अपने पीठासीन अधिकारी महोदया के आदेश को न केवल चुनौती दी वरन अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतते हुये अनुशासनहीनता का भी परिचय दिया, जो कदाचरण की श्रेणी में आता है। अतः आप धारा 3 सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के अन्तर्गत दोषी हैं।

पंचमः— यह कि दिनांक 22/08/2000 के अपने स्पष्टीकरण में आप ने कहा है कि पत्रावलियां जब पीठासीन अधिकारी महोदया के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी तो उन्होंने उससे कहा था कि चूंकि उसका लेख सही नहीं है, अतः आदेश पत्र पीठासीन अधिकारी के द्वारा ही लिखा जायेगा। इसी कारण उसे उसके द्वारा आदेशपत्र नहीं लिखा गया, और पत्रावली आलमारी में ही रखी रही, जिसके कारण नोटिस जारी नहीं किया जा सका। पीठासीन अधिकारी महोदया ने इस बात से इन्कार किया कि उन्होंने आप से कभी यह कहा हो कि चूंकि उसका हस्तलेख खराब है, इसलिए वह स्वयं आदेश पत्र लिखेंगी। यदि ऐसा कोई निर्देश पीठासीन अधिकारी महोदया द्वारा दिया गया होता तो यह असंभव था कि आप अन्य लगभग पांच सौ पत्रावलियों में आदेश पत्र लिखते। इसके विपरीत आप ने पूर्व विभागीय कार्यवाही में कहा था कि आदेश पत्र लिखना पीठासीन अधिकारी महोदया का निजी दायित्व है, और उनका आदेश पत्र लिखने से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार आप ने अपने कर्तव्यों

के प्रति अनुशासनहीनता का परिचय दिया है जो कदाचरण की श्रेणी में आता है। अतः आप धारा 3 सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के अन्तर्गत दोषी हैं।

अष्ठम:— *यह कि वादकारीगण प्रतिदिन आकर पीठासीन अधिकारी महोदया से शिकायतें इस बात की करते थे कि उनके द्वारा दाखिल तलबाने आप के द्वारा लगातार गायब कर दिये जाते रहे हैं। वादकारीगण की यह भी शिकायत है कि वे पहले भी कई बार बीस—बीस, पच्चीस—पच्चीस रूपये के तलबाने दाखिल कर चुके हैं। इस प्रकार आप ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरती है, जो कदाचरण की श्रेणी में आता है। अतः आप धारा 3 सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के अन्तर्गत दोषी हैं।"*

It is well settled law that the delay in completion of the present departmental proceedings was not wholly attributable to the delinquent employee but it was equally attributable to the department. Due to such unreasonable delay, the delinquent employee naturally suffered a lot because he and his family have to survive only on suspension allowance for a period of about 16 years.

Hon'ble Supreme Court has observed in several cases that it is duty of the employer to ensure that the departmental enquiry initiated against the delinquent employee is concluded within the shortest possible time by taking priority measures. In cases, where the delinquent is placed under suspension during the pendency of such enquiry then it becomes more imperative for the employer to ensure that the enquiry is concluded in the shortest possible time to avoid any inconvenience, loss and prejudice to the rights of the delinquent employee.

In **Prem Nath Bali Vs. Registrar, High Court of Delhi, Civil Appeal No. 958 of 2010 decided on 16.12.2015**, Hon'ble Supreme Court has observed that :

"We are of the considered opinion that every employee (whether State or private) must make sincere endeavour to conclude the departmental enquiry proceedings, once initiated against the delinquent employee within a reasonable time by giving priority to such proceedings and as far as possible it should be concluded within six months as an outer limit. "

At this stage, considering the period of suspension of delinquent employee, order of suspension dated 26.05.2001, charges leveled against delinquent employee and law laid down by the Hon'ble Supreme Court; I

am of the view without going through the gravity of charges, the suspension order dated 26.05.2001 is hereby revoked. He is reinstated with immediate effect.

Inform all concerned.

23.5.17.

(Sanjay Kumar Pachori)
District Judge,
Allahabad.

Dated : May 23, 2017

Copy to :
1. System Officer, Computer Center, District Court Allahabad.
2. Officer-in-Charge Administration
3. Concerned offices.
4. Bill Section.
5. Admin. Clerk.
6. In-charge C.A.O.

23.5.17

Administrative Officer,
District Court, Allahabad